



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

मं. 200] नई दिल्ली, शुक्रवार, विसम्बर 15, 1967/अग्रहायण 24, 1889

No. 200] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 15, 1967/AGRAHAYANA 24, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ तंत्रिया वी जाती है जिससे कि यह अलग संक्ष लक्ष के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation.

## MINISTRY OF COMMERCE

## RESOLUTION

New Delhi, the 15th December 1967

No. 16(5)Plant(B)/67.—In Government's letter No. 16(2)Plant(B)/65 dated the 28th October, 1966, the Tariff Commission was requested under section 12(d) of the Tariff Commission Act, 1951, to conduct necessary enquiries in regard to the cost of production of raw rubber and to submit a report on the fair prices for its different grades and qualities. The Commission has submitted its report wherein the following recommendations have been made:—

- (1) An census of actual area under rubber with special reference to mature area should be undertaken by the Rubber Board with the assistance of Revenue authorities in order to make more reliable data available.
- (2) The Rubber Boards estimate of an average yield of 294 Kg. per hectare (262 lbs per acre) in the small holdings sector is an under-estimate. It is desirable to devise more stringent measures of checking transactions by dealers to ensure not only the correct data of production but also the assessment of the cess actually due.
- (3) The existing differentials in the prices of grades of rubber should be retained as they are.

(4) For an orderly marketing of indigenous production, it is necessary that imports should come in regular monthly instalments and not as has happened during the latter half of 1966 in large quantities, just when the tapping of trees is at its height.

(5) The Rubber Board should be consulted both on the volume and programming of imports. The imports should be evenly spread out over the year.

(6) The expenses incurred by a planter for replantation should be considered as capital investment and this replantation cost must be earned through the sale of rubber. One half of the development expenses (viz., Rs. 11.67) should be included in the retention price of the grower. A new scale of subsidy is recommended to be paid to the growers to enable them to meet the cost of replantation which will not be fully recovered through the retention price.

(7) A price of Rs. 415 per 100 kgs. should be fixed as the price to be retained by the growers f.o.b. Cochin for R.M.A. 1 grade rubber. This will be exclusive of sales-tax and cess. The prices for other grades and for preserved latex will be fixed after adjustment of grade differentials indicated by the Commission.

(8) A reduction in the cess needs to be considered by Government.

(9) The rehabilitation allowance provided for replantation in Kanyakumari district of Madras State is not on a par with that in the rest of the State, and needs to be looked into by the Government of Madras.

2. Government accept recommendations (1) and (3) above.

3. Government have taken note of the recommendation (2) above.

4. Government have taken note of the recommendations (4) & (5) above and steps will be taken to implement them to the extent practicable.

5. Recommendation (6) is under examination by the Government.

6. Government have already accepted recommendation (7) in para 1 of their Resolution No. 19(15)Plant(B)/67 dated the 26th September, 1967 published in the Gazette of India Extraordinary dated the 27th September, 1967.

7. Keeping in view the expansion of the developmental and research activities of the Rubber Board for further development of the rubber plantation industry, Government do not consider it feasible to reduce the existing rate of cess on rubber, viz., 30 Paise per kg., as suggested by the Commission in recommendation (8) above.

8. Government have brought the recommendation (9) to the notice of the Government of Madras for necessary action.

---

Orders

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. BANERJEE, Dy. Secy.

## वाणिगण मंत्रालय

## संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसंबर 1967

सं० 16(5)/प्लाण्ट (बी)/67. — ईरिक आयोग अधिनियम, 1951 की द्वारा 12(८) के अधीन सरकार के पत्र मंड्या 16(2) प्लाण्ट (बी)/65 दिनांक 28 अक्टूबर, 1960 के द्वारा ईरिक आयोग से कच्चे रबड़ की उत्पादन लागत के बारे में जांच करने और इसकी विभिन्न श्रेणियों और किस्मों के लिए उत्तित मूल्य के मंबंध म प्रतिवेदन दले का अनुरोध किया गया था। आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है जिसमें निम्नलिखित निपारिशों की गई हैं।

- (1) रबड़ बोर्ड द्वारा राजनीव अधिकारियों की महाया १ मेर रबड़ के वास्तविक क्षेत्र, विशेषतः पूर्व विकसित क्षेत्र की गणना की जानी चाहिए ताकि अधिक विवरणीय आकड़े प्राप्त हो सकें।
- (2) रबड़ बोर्ड का प्रति हेक्टर 294 कि०ग्रा० (प्रति एकड़ 26.2 पौड़) की औसत उपज का अनुमान कम है। यह बोर्डनीय है कि ध्यापारियों के व्यापारिक कारोबार की जांच करने के अधिक कठोर उपाय निकाले जाएं जिनसे न केवल उत्पादन के सही आकड़े मिलना अपितु वास्तव में देय उपकर का आकलन करना भी सुनिश्चित हो सके।
- (3) रबड़ की श्रेणियों के मूल्यों में विद्यमान अंतर यथावत रखे जाने चाहिए।
- (4) स्वदेशी उत्पादन के व्यवस्थित विकास के लिए यह आवश्यक है कि श्रायात नियमित मासिक किस्तों में आने चाहिए न कि इस तरह जैने कि 1966 के उत्तरार्द्ध में हुआ कि बहुत बड़ी मात्रा उन समय आई जबकि पेड़ों की चुंबाई का कार्य चरमसीमा पर था।
- (5) आयातों के फरिणाम और उनहे कर्य-अभ के मंबंध में रबड़ बोर्ड का परामर्श लिया जाना चाहिए, आयात समान मात्रा में वर्षे भर में किये जाने चाहिए।
- (6) उत्पादकों द्वारा पुनर्रॉपण पर किए गए खर्चों को पूँजीगत निवेश माना जाना चाहिए और इन पुनर्रॉपण लागत को रबड़ की विक्री मेर उपर्युक्त किया जाना चाहिए। विकास अर्थों का अद्वितीय (अर्थात् 11.67 रुपए) उत्पादकों के धारण मूल्य में नम्मिलित किया जाना चाहिए। उत्पादकों को दिए जाने वाले उपदान की नई दर की दिफारिश की जाती है ताकि वे पुनर्रॉपण की लागत को पूरा कर सके और भारण मूल्य के माध्यम से पूरी नहीं की जा सकें।
- (7) उत्पादकों द्वारा धारण के लिए आर० एम० ए० (१) श्रेणी के रबड़ का कोकीन में जहाज तक निःशुल्क प्रति 100 किमा 415 रुपए मूल्य नियत किया जाना चाहिए। इसमें विक्री करतथा उपकर शामिल नहीं होगा। अन्य श्रेणियों के रबड़ तथा परिरक्षित रबड़-दुरुध के मूल्य आयोग द्वारा बताए गये श्रेणी विभेदों का दमजन करने के फलात् नियत किए जायेंगे।
- (8) सरकार द्वारा उपकर में कमी करने पर विचार किया जाना अपेक्षित है।
- (9) सरकार राज्य के कन्याकुमारी जिले में पुनर्रॉपण के लिये दिया जाने वाला पुनर्स्थापन भस्ता राज्य के शेष भागों के समान नहीं है और इस विषय पर सरकार द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है।

2. सरकार उपर्युक्त निकारिश (1) तथा (3) को स्वीकार करती है।
3. रकार ने उपर्युक्त निकारिश (2) नोट करती है।
4. रकार ने उपर्युक्त निकारिश (4) तथा (5) के बेख लिया है, और जहाँ तक व्यवहार्य होगा उन्हें कार्यनित करने के लिये बबम उठाये जायेगे।
5. निकारिश (6) सरकार के विचाराधीन है।
6. सरकार ने निकारिश (7) को भारत के अनाधारण राजपत्र (दिनांक 27 मित्सबर, 1967 में प्रकाशित अपने संकरण में 19(15) 'लाइट (बी) / 67 दिनांक 26 मित्सबर, 1967 के पैरा 1 के द्वारा पहने ही स्वीकार कर लिया है।
7. रबड़ बागान रद्दोग के श्रीर बिकास के लिए रबड बोड़ की विकार रामक तथा गवेषणात्मक गतिविधियों के विस्तार को यन्न में रखते हुये रकार रबड पर विद्यमान उपकर के दर, अर्थात् 30 पैसे प्रति किलो को कम करना, जैसा कि उपर्युक्त निकारिश (8) में प्रायोग द्वारा नियमित दिया गया है, व्यवहार्य नहीं समझती।
8. रकार के मालास रकार का यान उपर्युक्त निकारिश (9) की ओर आक्रमणक कार्यवाही के लिये दिलाया है।

### आवेदन

आदेश दिया जाता है कि इस सकरप को मधी मम्बद्दों को भेजा जाए।

यह भी आवेदन दिया जाता है कि इस सकरप को अंतर्जनक सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

एम० वनजी

उप-रचित, भारतम रकार।